

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 335 बेमेतरा, शनिवार 01 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

बस्तर के प्रतिनिधियों ने देखा राष्ट्रपति भवन, बस्तर की संस्कृति का हुआ भव्य सम्मान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के स्वागत से बस्तर का प्रतिनिधिमंडल हुआ अभिभूत

रायपुर। राष्ट्रपति भवन में बस्तर के प्रतिनिधिमंडल के लिए एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक क्षण साकार हुआ। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर से पहुंचे परगना माझियों, चालकियों, बस्तर पंडुम के जनजातीय कलाकारों तथा समाज प्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने सभी अतिथियों का शॉल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मान किया और बस्तर की समृद्ध जनजातीय परंपरा एवं संस्कृति के प्रति अपना विशेष स्नेह व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा

संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन और पहल से आयोजित इस विशेष यात्रा ने बस्तर के जनजातीय समाज को देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रपति भवन में बस्तर की संस्कृति का जो सम्मान हुआ, उसने प्रतिनिधिमंडल के प्रत्येक सदस्य को गौरव और आत्मविश्वास से भर दिया। प्रतिनिधिमंडल के लिए सबसे भावुक और प्रेरणादायी क्षण उस समय आया, जब राष्ट्रपति ने एक मेजबान की भूमिका निभाते हुए स्वयं अपने हाथों से सभी अतिथियों को भोजन परोसा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिनिधियों को दाल परोसी, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सभी को मिठाई परोसकर उनका स्वागत-सत्कार



किया। राष्ट्रपति भवन में आत्मीयता और अपनत्व से भरे इस दृश्य ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को भावविभोर कर दिया। बस्तर से आए जनजातीय प्रतिनिधियों ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया।

इस अवसर पर एक और ऐतिहासिक पल तब आया, जब बस्तर पंडुम के विजेता कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन परिसर में अपनी पारंपरिक लोकगीत और लोकनृत्य की प्रस्तुति दी। बस्तर की लोक संस्कृति, वेशभूषा और पारंपरिक कला का यह अनुपम प्रदर्शन उपस्थित सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना और राष्ट्रपति भवन पहली बार बस्तर की सांस्कृतिक रंगत से सराबोर हो उठा। माहौल ऐसा हुआ कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित बस्तर कमिश्नर डीमन सिंह, पूर्व बस्तर आई जी सुंदरराज पी और सभी अधिकारी भी लोकनृत्य में झुमने लगे। राष्ट्रपति से बात करते हुए कांकेर के पद्म सम्मान से अलंकृत काष्ठ कलाकार अजय मंडवी ने कहा कि बस्तर की कला और संस्कृति विश्व में अद्वितीय है। लंबे समय

तक भय और असुरक्षा के वातावरण के कारण इस विरासत को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि अब सुरक्षा बलों के साहस और सरकार के प्रयासों से बस्तर में शांति का वातावरण स्थापित हुआ है। जिससे कलाकारों को अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रखने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में बस्तर की कला वैश्विक पहचान बनाएगी। गढ़िया-लोहंडीगुड़ा परगना के मांझी बलराम कश्यप ने राष्ट्रपति महोदया को बताया कि पहले बस्तर के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2027 में रायपुर में प्रस्तावित ‘लखपति दीदी सम्मेलन’ में शामिल होने का दिया आमंत्रण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प तथा राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बदलते छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए राज्य की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुरक्षा, विश्वास और विकास की समरूपता रणनीति के परिणामस्वरूप बस्तर आज व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। दशकों तक नक्सल हिंसा और विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाला यह क्षेत्र

अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, बिजली, हवाई संपर्क, आजीविका, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस परिवर्तन को स्थायी बनाते हुए बस्तर को विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ना है। राजनांदगांव में 10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना के लिए शीघ्र मंजूरी का अनुरोध मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग 10,500 करोड़ की गैस आधारित यूरिया परियोजना की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गई है तथा राज्य सरकार के स्तर की आवश्यक स्वीकृतियां भी पूरी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के



स्थापित होने से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता और बेहतर होगी। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक निवेश, प्रत्यक्ष एवं स्वीकृतियां भी पूरी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के

ग्रिड पहुंचाना संभव नहीं हो पाया था और वर्तमान में ऑफ-ग्रिड माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इन गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थायी विद्युत आपूर्ति से इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, आजीविका और लघु उद्यमों के विस्तार को गति मिलेगी तथा दूरस्थ अंचलों में विकास की प्रक्रिया और मजबूत होगी। रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना का किया अनुरोध मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रायपुर अथवा बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल

का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय वनस्पतियों एवं पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान की समृद्ध विरासत है। राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से चिकित्सा, अनुसंधान, शिक्षा और औषधीय वनस्पतियों पर आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नई संभावनाएं विकसित होंगी। 5,542 गांवों तक पहुंच रहा विकास, लगभग 39 लाख लोगों को लाभ मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री के समक्ष ‘बस्तर विजन’ की विस्तृत जानकारी रखते हुए बताया कि ‘नियद नेस्त्रा नार 2.0’ और ‘बस्तर मुहिम’ के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में शासन की योजनाओं और सेवाओं का व्यापक क्रियान्वयन किया

जा रहा है जिससे लगभग 39 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राशन, आयुष्मान भारत, जनधन खाते, वनाधिकार, प्रधानमंत्री आवास सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ और पूर्व में अत्यधिक संवेदनशील रहे गांवों में प्रशासन की पहुंच बढ़ने से शासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। 421 बंद स्कूल फिर खुले, ओरछा और जगरगुंडा में बर्नेगी एजुकेशन सिटी मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में आए परिवर्तन की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़े 421 स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया है।

जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक लोकसभा में बिना चर्चा के पारित

नयी दिल्ली। लोकसभा में शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित किया गया। इस विधेयक में देरी से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए नियम कड़े किये गये हैं। एक साल से अधिक की देरी से लेकन दो साल के भीतर जन्म या मृत्यु पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य था जो सत्यापन के बाद यह आदेश देने के लिए प्राधिकृत है। वहीं, दो साल से अधिक की देरी की स्थिति में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही जन्म या मृत्यु पंजीकरण होगा। वर्तमान में एक साल बाद किसी भी समय तक संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश ही



पर्याप्त था और दो साल से ऊपर के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही जब पुनः शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य 20 जुलाई को संसद भवन के निकट प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही निभारित करने और इसके लिए आदेश देने वाले का नाम सदन में बताने की मांग करते हुए फिर हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर शोरगुल कर रहे थे। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने इसी बीच विधायी दस्तावेज पटल पर रखवाये।

रेलवे भर्ती में में देनी होगी बीमारी की पूरी जानकारी, तथ्य छिपाने पर नौकरी हो सकती है रद्द

नयी दिल्ली। रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब प्रत्येक अभ्यर्थी को चिकित्सकीय परीक्षण से पहले अपने स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी शपथपूर्वक देनी होगी। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे चिकित्सकीय नियमावली के तहत स्व-घोषणा पत्र का नया प्रारूप लागू कर दिया है, जो अब सभी आगामी भर्तियों में अनिवार्य होगा। रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लिया है। संशोधित व्यवस्था में सहायक लोको पायलट भर्ती तथा टुट्टि सुधार के लिए कराई जाने वाली लेज़र नेत्र शल्यक्रिया से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को यह बताना होगा कि क्या वे कभी हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, दमा, क्षय रोग, मिर्गी, मानसिक रोग अथवा किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हैं। उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या वे लंबे समय तक किसी बीमारी का उपचार कराते रहे हैं, कभी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, फिर में गंभीर चोट लगी है या आंखों की कोई शल्यक्रिया कराई



है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को यह भी घोषित करना होगा कि क्या वे मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का उपचार करा रहे हैं, उन्हें हकलाने या बोलने में किसी प्रकार की समस्या है। वे मादक पदार्थों या शराब का सेवन करते हैं अथवा उन्हें पहले किसी सरकारी नौकरी में चिकित्सकीय आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है। स्व-घोषणा पत्र में अभ्यर्थी को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा दी गई सभी जानकारीयें सत्य और पूर्ण हैं। साथ ही यह भी घोषित करना होगा कि उसने किसी बीमारी के आधार पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र या पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं किया है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी बीमारी या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी गृह सचिव को चार अगस्त को किया तलब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब करते हुए पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को चार अगस्त 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने हिरासत में मौत के मामले में अब तक की गई आपराधिक कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज किए जाने की स्थिति पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। मामला 34 वर्षीय श्रवण सूर्यवंशी की मौत से जुड़ा है। उनकी पत्नी लहया बाई ताम्रकार तथा उनकी दो नाबालिग बेटियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत हलफनामे पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हिरासत में हुई मौत के मामले में एफ आईआर दर्ज करने अथवा आपराधिक जांच प्रारंभ करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

गहरे समुद्र में तेल एवं गैस की खोज के लिए 84 हजार करोड़ रुपये की ‘समुद्र मंथन’ योजना को मंजूरी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र में तेल एवं गैस अन्वेषण में तेजी लाने के लिए शुक्रवार को 84 हजार करोड़ रुपये की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की समुद्र मंथन योजना के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक के कार्यान्वयन हेतु 84,084 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तेजी से गैस और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ रही है, यह योजना परिवर्तनकारी साबित होगी। मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से इसकी घोषणा की थी।

उन्होंने देश की विशाल अपतटीय ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए आधुनिक युग के समुद्र मंथन का आह्वान किया था। वैष्णव ने बताया कि इस योजना के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से के तहत आंकड़े एकत्र किये जायेंगे कि भारतीय समुद्री सीमा में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की समुद्र मंथन योजना के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक के कार्यान्वयन हेतु 84,084 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तेजी से गैस और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ रही है, यह योजना परिवर्तनकारी साबित होगी। मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से इसकी घोषणा की थी।

रायपुर में पुलिस का सत्यापन अभियान आठ संदिग्ध मिले, फरार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस कमिश्नरेंट के मध्य जोन ने शुक्रवार को बीएसयूपी कॉलोनिनों में विशेष चेकिंग एवं सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब 350 मकानों की जांच की गई, जिसमें आठ संदिग्धों की पहचान हुई। वहीं मारपीट के मामले में पिछले कुछ महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, यह अभियान शुक्रवार सुबह 4:30 बजे से नौ बजे तक थाना तेलीबांधा क्षेत्र के बीएसयूपी लाभांडी, बीएसयूपी तेलीबांधा

(मरीन ड्राइव) और देवार डेरा क्षेत्र में चलाया गया। कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (मध्य) तारकेश्वर पटेल के निर्देशन और सहायक पुलिस आयुक्त (सिविल लाइन) रमाकांत साहू के नेतृत्व में की गई। अभियान में थाना तेलीबांधा एवं पुलिस लाइन के 80 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे। इस दौरान किरायेदारों के पुलिस सत्यापन, बिना सत्यापन के किरायेदार रखने वाले मकान मालिकों और बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान मिले सभी संदिग्धों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इनमें मारपीट के एक मामले में

फरार आरोपी भी शामिल है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम ने स्थानीय नागरिकों को अपराध नियंत्रण के लिए ‘समाधान’ मोबाइल ऐप की जानकारी दी और किरायेदारों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन करने की अपील की। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील भी की गई। रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अपने घरों में किरायेदार रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन जरूर कराएं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी डायल 112 अथवा नजदीकी पुलिस थाने में दें।

गाज़ा के शासन-प्रणाली को बुनियादी रूप से बदल देगा ट्रंप ने हमास के निशस्त्रीकरण के ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा में हमास और अन्य सभी सशस्त्र समूहों के निशस्त्रीकरण के एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह समझौता संघर्ष को खत्म करने और उस इलाके में एक नई फ़िलिस्तीनी सरकार का गठन करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अपने ‘ट्रुथ सोशल’ प्लेटफ़ॉर्म पर गुरुवार को घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह समझौता उनकी अध्यक्षता वाले ‘इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस’ द्वारा किया गया है और इसे सावधानीपूर्वक तैयार किए गए चरणों में लागू किया जाएगा। ट्रंप ने लिखा, आज, ‘इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस’ ने गाज़ा में हमास और अन्य सभी हथियारबंद गुटों के पूरी तरह से निशस्त्रीकरण के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बनाई है। यह



स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता इज़रायल की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गाज़ा के शासन-प्रणाली को बुनियादी रूप से बदल देगा। उन्होंने कहा, यह समझौता गाज़ा में एक नई फ़िलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक अहम

कदम है, जो फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए ‘बोर्ड ऑफ़ पीस’ के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही, इज़रायल को वह सुरक्षा मिलेगी जिसका वह हकदार है क्योंकि गाज़ा का इस्तेमाल अब आतंकी हमलों के अड्डे के तौर पर नहीं किया जाएगा। ट्रंप के अनुसार, यह समझौता चरणों में लागू किया जाएगा। जैसे-जैसे निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इज़रायली सेनाएं गाज़ा से हट जाएंगी और एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालेगा, जो हाल ही में गठित फ़िलिस्तीनी पुलिस बल के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप ने इस बात पर भी बल दिया कि सात अक्टूबर जैसा हमला दोबारा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत, गाज़ा आखिरकार एक ऐसी नई फ़िलिस्तीनी सरकार के हाथों में होगा जो

अपने लोगों की सेवा करेगा। इस घटनाक्रम को अपनी शांति पहल में एक अहम पड़ाव बताते हुए ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के साथ-साथ अपने प्रशासन के सदस्यों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस समझौते को कराने में मदद की। अमेरिका और ‘बोर्ड ऑफ़ पीस’ के अधिकारियों ने कहा कि इसे लागू करना महीनों की बहुत नाज़ुक बातचीत के बाद हुआ है और यह एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसे लागू करना कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा और हर चरण पर इसकी पुष्टि की जाएगी। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने हर कदम पर इज़रायल के साथ तालमेल बिठाया लेकिन उन्होंने यह भी माना कि इज़रायली अधिकारियों को इस बात पर शक था कि क्या हमास पूरी तरह से हथियार छोड़ देगा।



संपादकीय

जरूरत इस बात की है कि न केवल परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने, बल्कि व्यापक शैक्षिक सुधारों के प्रति ईमानदार इच्छाशक्ति के साथ सरकार कदम आगे बढ़ाए। एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही खुबसूरती है कि अगर किसी मसले पर सरकार के रुख की वजह से जनता के बीच असंतोष और विरोध की भावना बढ़ रही हो, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो पिछले कुछ समय से

नीट 2026 में प्रश्नपत्र लीक होने के मसले पर लोगों के भीतर उभरे व्यापक क्षोभ और विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का आखिर इस्तीफा देना लोकतांत्रिक परंपरा की ही अगली कड़ी है। हालांकि सरकार ने अगर इस संबंध में समय रहते ठोस फैसला किया होता और जनता के बीच स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की होती, तो शायद लोगों के बीच आक्रोश का दायरा इतना नहीं फैलता, जिसने सरकार की मंशा पर गहरे सवाल

नीट 2026 विवाद के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार की चुनौती

उठाए।प्रश्नपत्र लीक होने की घटना के उजागर होने के बाद से ही समूचा सरकारी तंत्र एक तरह से कठघरे में खड़ा था और लोगों ने सरकार से जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ ठोस कार्रवाई की मांग की थी। मगर सरकार ने इस मसले पर तब तक उपेक्षा और उदासीनता का रुख अपनाए रखा, जब तक काकरीच जनता पार्टी के आह्वान के बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में इस मुद्दे पर व्यापक जनांदोलन नहीं खड़ा हो गया।विचित्र

यह भी है कि प्रश्नपत्र लीक होने की घटना की गंभीरता और उस पर लोगों के बीच पसरते आक्रोश की तीव्रता का अंदाजा होने के बावजूद सरकार ने न तो ठोस कार्रवाई करने का संकेत दिया और न ही आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे विद्यार्थियों से संवाद कायम करने की कोशिश की। इसके उलट जंतर मंतर पर जमे प्रदर्शनकारियों ने जब ‘संसद मार्च’ के आह्वान के जरिए अपनी मांग और आवाज को आगे बढ़ाना चाहा, तो उन्हें

रोकने के लिए सरकार ने एक तरह पुलिस को खुला छोड़ दिया गया। नतीजतन, पुलिस ने हर मानवीय तकाजे को ताक पर रख कर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और बेरहमी से लाठीचार्ज किया।सरकार का यह रवैया लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को चोट पहुंचाने वाला था। इसी के बाद न केवल दिल्ली में, बल्कि देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह एक तरह से इस समूचे मुद्दे पर

सरकार के अपरिपक्व रवैये का सबूत था, जिसके तहत आंदोलनकारियों से संवाद करके समस्या का समाधान निकालने के बजाय बल प्रयोग के जरिए उनका दमन करने की कोशिश की गई।जाहिर है, सरकार का यह रुख एक और अलोकतांत्रिक तथा गैरजिम्मेदार कदम के रूप में देखा गया और सवाल उठे कि क्या इस तरह असहमत होने और विरोध करने के संवैधानिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है।

29 गुरु पूर्णिमा पर विशेष आलेख

गुरु होता है आध्यात्मिक ज्ञान का पोषक

आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की प्रबल इच्छा ही वह ताकत बन गई है जिसके चलते मैं गुरु के विषय में अपने विचारों को कलमबद्ध करने बैठा हूं । मैं तो ईश्वर की कृपा ही मानता हूं कि मुझे इतने अच्छे गुरु या कहूँ गुरुओं का सानिध्य मिला जिनके आशीर्वाद ने मुझे एक दिशा प्रदान की । मैने यह अनुभव किया है कि एक सच्चा गुरु निः स्वार्थ प्रेम , ज्ञान और सादगी का प्रतीक होता है । लालच जैसे अवगुण से कहीं दूर गुरु अपने कर्तव्य को धर्म मानते हुए ही आचरण करते हैं । वे कभी भी व्यवहार को व्यापार नहीं बनने देते । उनके हृदय में अहंकार नहीं होता । उनके वचन वेदों और शास्त्रों के अनुकूल होते हैं । वे ही इस मृत्युलोक में अच्छे - बुरे का ज्ञान कराकर सही मार्ग पर अपने शिष्यों को प्रशस्त करते हैं । सांसारिक लाभ या धन की अपेक्षा उन्हें दूर -दूर तक छू नहीं पाती है । एक गुरु का उद्देश्य शिष्य के भीतर छिपे आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करना ही होता है । यह भी शाश्वत सत्य है कि गुरु का ज्ञान और उनके द्वारा दिए गए उपदेश प्रामाणिक होते हैं । दिखावा और पाखण्ड उनके विचारों को दूषित नहीं कर पाते हैं । अनुशासन और श्रेष्ठ चरित्र ही गुरु की महिमा माने जाते हैं । एक गुरु कभी भी अपने शिष्य को अंधेरे में नहीं रखता । सदेहों का समाधान कर वे अपने शिष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं ।

आज की बदली परिस्थितियों में गुरु और शिष्य के संबंध नाग्य हो चले हैं ! अब न तो गुरुकुल की परंपरा रही और न ही समर्पित गुरुओं का सानिध्य ! आज के समय में हमारी पीढ़ी ने नए गुरु की खोज कर ली है , जिसे ÷ गुगल ÷ गुरु के नाम से जाना जाता है ! हम यदि अपने बच्चों को कोई सीख देना चाहें तो वे इसके लिए सहज रूप से तैयार नहीं होते हैं ! गुगल ने जो कुछ बता दिया वही पत्थर की लकरी बन जाती है ! हमारी पीढ़ी इस बात को मानने तैयार नहीं कि जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत जरूरी है । आज मैं अपने इस लेख के माध्यम से दुस्साहस करते हुए वर्तमान पीढ़ी को गुरु की महिमा से अवगत कराना चाहता हूं । हमने हमेशा से ही गुरु महिमा का वर्णन अपने बुजुर्गों से सुना है । वे कहा करते थे जिसका कोई गुरु नहीं , उसका उद्धार नहीं। एक छोटा सा कथानक याद आ रहा है - ÷ एक बार सुखदेव ऋषि अपनी सिद्धि की शक्ति के बल पर उड़ान भरते हुए स्वर्ग पहुंच गए । भगवान विष्णु ने सुखदेव ऋषि के स्वर्ग प्रवेश को यह कहते हुए रोक दिया कि आका अभी तक कोई गुरु नहीं है ! विवश होकर सुखदेव ऋषि को धरती पर लौटना पड़ा ! बाद में उन्होंने राजा जनक को अपना गुरु बनाया और स्वर्ग में स्थान पाया ।

इस संसार में गुरु ही वह व्यक्ति है जो मनुष्य को जन्म -मरण के रोग रूपी अंधकार से मोक्ष रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है । समाज में व्याप्त अंधविश्वास , रूढ़िवादिता , पाखंडवाद और अंध भक्ति की गहरी नींद से जगाकर मानवीय समाज को वास्तविक और प्रमाणिक भक्ति का मार्ग एक गुरु ही दिखाता है । इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानी और दृश्य बताते हैं कि इस धरती पर जितने भी महापुरुष हुए , सभी ने गुरुओं की कृपा पाई । भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्रीराम हों या फिर श्रीकृष्ण और गुरुनानक ही क्यों न हों , सभी के गुरुओं की कहानी हम पढ़ते आ रहे हैं । सभी ने अपनी अंतिम साँस तक गुरु की मर्यादा में रहकर उनकी भक्ति और पूजा की । भगवान श्रीराम ने वशिष्ठ जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाकर उनसे दीक्षा ग्रहण की । आज की पीढ़ी यह बातना चाहती है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने जो कुछ सीखा वही सर्वथा

सत्य है ! इसे मैं कुएं के मेंढक की सोच ही मानता हूं । आज के आधुनिक और तकनीकी युग में भी , जहां जानकारी आसानी से उपलब्ध है , एक सच्चे मार्गदर्शक या गुरु की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । गुरु केवल किताबी ज्ञान ही नहीं ,बल्कि जीवन जीने की सही कला , नैतिक मूल्य और अनुशासन भी सिखाता है । एक सच्चा गुरु ही हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं । असमंजस की स्थिति में गुरु का मार्गदर्शन हमारा सबसे बड़ा संबल बनकर सामने आता है । गुरु का सानिध्य ही एक व्यक्ति को विनम्रता , धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों से परिपूर्ण



करता है ।

हमारे जीवन में एक गुरु होना कितना जरूरी है , इसे एक कथानक से समझा जा सकता है । पोरस को जब बंदी बनाकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया , तो सिकंदर ने पोरस से पूछा - आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए ? पोरस ने बड़ी ही सहजता से कहा - ÷ एक राजा , दूसरे राजा के साथ जैसा बर्ताव करता है , आप भी मेरे साथ वैसा ही करें ।÷ पोरस के उत्तर से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे न केवल रिहा किया बल्कि उसका राज्य भी लौटा दिया और खुद अपने देश लौट गया ! ठीक इसी तरह मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद वही प्रश्न किया कि -मुझे तुम क्या अपेक्षा रखते हो ? पृथ्वीराज चौहान ने भी पोरस से मिलता - जुलता ही उत्तर दिया । पृथ्वीराज चौहान ने कहा - मैने तुन्हें अनेक बार क्षमादान दिया है , इसलिए तुन्हें भी मेरे साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए । पृथ्वीराज की इस मांग के बाद मोहम्मद गोरी ने उसकी आँखें फोड़ दीं और मृत्यु दंड की सजा सुना दी ! दोनों घटनाओं में समानता के बावजूद परिणाम अलग रहे ! जानते हैं ऐसा क्यों हुआ ? वह इसलिए कि सिकंदर के चरित्र और व्यवहार को उसके गुरु और मार्गदर्शक अरस्तु (एरिस्टोटल) ने अपने ज्ञान से तराशा था । इसके विपरीत मोहम्मद गोरी की संगत ऐसे किसी गुरु या मार्गदर्शक से नहीं थी ! वह जंगलियत में पैदा हुआ ।

जंगलियत में जिया और उसी जंगलियत में मर गया !

सामान्यतः यह देखने में आ रहा है कि लोग गुरु और शिक्षक को एक ही तराजू में तौलते हैं । भारतीय संस्कृति के मान से देखा जाए तो इन दोनों शब्दों में सूक्ष्म और महत्वपूर्ण अंतर दिखाई पड़ता है । स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो हमें किसी विषय विशेष अथवा कौशल का ज्ञान प्रदान करता है । शिक्षक का कार्य क्षेत्र शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ाव रखते हुए शैक्षणिक ही हुआ करता है । शिक्षक ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं तथा अपना विद्यार्थियों को उस ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्रदान करते हैं । मसलन गणित का शिक्षक



जहां सूत्रों की जानकारी प्रदान करता है वहीं हिंदी भाषा का शिक्षक व्याकरण और साहित्य का ज्ञान प्रदान कर अपना कर्तव्य निभाता है ।

अब यदि बात की जाए ÷ गुरू÷ की तो एक गुरु का संबंध अपने शिष्य के साथ कहीं अधिक गहराई लिए होता है । गुरु का काम किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि वे अपने शिष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं । वे शिष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं । उनमें नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं । साथ ही अपने शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं । गुरु और शिष्य का संबंध आजीवन बना रहता है । गुरु अपने शिष्य के हर पहलु पर अपनी शिक्षा का प्रभाव डालते रहते हैं । गुरु का मार्गदर्शन केवल शैक्षणिक नहीं होता बल्कि वह जीवन दर्शन , नैतिकता , धर्म और आध्यात्मिकता तक विस्तार लिए होता है । एक गुरु अपने शिष्य को केवल क्या पढ़ना है ? यह नहीं बताते वरन कैसे जीना है , यह भी सिखाते हैं । गुरु का उद्देश्य शिष्य को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाना होता है । गुरु ही अपने शिष्य की आत्मा को पोषित करता है ।

डॉ सूर्यकांत मिश्रा

राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

9425559291

एग्रो-वोल्टिक्स- खाद्य, ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा का एकीकृत वैज्ञानिक मॉडल

(**डॉ दीपक कोहली**)

एग्रो-वोल्टिक्स के पीछे कार्य करने वाला वैज्ञानिक दर्शन जीवविज्ञान और भौतिकी के अत्यंत सूक्ष्म एवं अंतर-संबंधी सिद्धांतों पर आधारित है। साधारणतया यह माना जाता है कि पौधों को जितनी अधिक सूर्य की रोशनी मिलेगी, वे उतनी ही तेजी से वृद्धि करेंगे, परंतु अन्वयन्त्रि विज्ञान के गहरे अध्ययन इस भ्रांति का निवारण करते हैं। तेजी से बढ़ती वैश्विक जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, कृषि योग्य भूमि में निरंतर कमी और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग ने मानव सभ्यता के सामने एक जटिल चुनौती खड़ी कर दी है, क्या एक ही भूमि से भोजन भी उगाया जा सकता है और ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकती है? लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि कृषि और सौर ऊर्जा परियोजनाएँ एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी हैं, क्योंकि दोनों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। किंतु विज्ञान ने इस द्वंद्व का एक अभिनव समाधान प्रस्तुत किया है, जिसे एग्रो-वोल्टिक्स या एग्रो-सोलर प्रणाली कहा जाता है। यह ऐसी वैज्ञानिक अवधारणा है, जिसमें एक ही खेत पर फसल उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों साथ-साथ किए जाते हैं। परिणामस्वरूप वही भूमि एक साथ अन्न, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण, तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यही कारण है कि आज एग्रो-वोल्टिक्स को भविष्य की सतत कृषि और हरित ऊर्जा का एकीकृत मॉडल माना जा रहा है। एग्रो-वोल्टिक्स के पीछे कार्य करने वाला वैज्ञानिक दर्शन जीवविज्ञान और भौतिकी के अत्यंत सूक्ष्म एवं अंतर-संबंधी सिद्धांतों पर आधारित है। साधारणतया यह माना जाता है कि पौधों को जितनी अधिक सूर्य की रोशनी मिलेगी, वे उतनी ही तेजी से वृद्धि करेंगे, परंतु वनस्पति विज्ञान के गहरे अध्ययन इस भ्रांति का निवारण करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश और तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, तो अधिकांश पौधों में फोटो-इनहिबिशन यानी प्रकाश-संश्लेषण में बाधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीव्र

किंतु विज्ञान ने इस द्वंद्व का एक अभिनव समाधान प्रस्तुत किया है, जिसे एग्रो-वोल्टिक्स या एग्रो-सोलर प्रणाली कहा जाता है। यह ऐसी वैज्ञानिक अवधारणा है, जिसमें एक ही खेत पर फसल उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों साथ-साथ किए जाते हैं। परिणामस्वरूप वही भूमि एक साथ अन्न, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण, तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यही कारण है कि आज एग्रो-वोल्टिक्स को भविष्य की सतत कृषि और हरित ऊर्जा का एकीकृत मॉडल माना जा रहा है। एग्रो-वोल्टिक्स के पीछे कार्य करने वाला वैज्ञानिक दर्शन जीवविज्ञान और भौतिकी के अत्यंत सूक्ष्म एवं अंतर-संबंधी सिद्धांतों पर आधारित है।

ऊष्मा के कारण पौधों की पत्तियाँ अपनी रक्षा के लिए रेशों को बंद कर लेती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण रुक जाता है और पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। सोलर पैनलों को जब एक वैज्ञानिक कोण और पारभासी दूरी पर स्थापित किया जाता है, तो वे नीचे उगई जाने वाली फसलों के लिए एक रक्षात्मक छत्र का कार्य करते हैं। यह आंशिक छाया पौधों को भीषण ताप-लहरों, चिलचिलाती धूप, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन और ओलावृष्टि जैसे मौसमी जोखिमों से बचाती है। परिणामस्वरूप, खेत के धरातल पर एक अनुकूल सूक्ष्म-जलवायु निर्मित होती है, जहाँ मिट्टी की नमी लंबे समय तक संरक्षित रहती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि एग्रो-वोल्टिक्स प्रणालियों के अंतर्गत कृषि में सिंचाई जल की खपत में तीस से चालीस प्रतिशत तक की अभूतपूर्व कमी आती है, जो भूजल के गिरते स्तर से जुड़ रहे क्षेत्रों के लिए एक जीवनदायिनी क्रांति से कम नहीं है। इस अंतर-विषयक प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसका सह-जैविक और परस्पर पूरक होना है, जहाँ कृषि और सौर पैनल एक-दूसरे की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। जहाँ एक ओर सोलर पैनल फसलों को अत्यधिक ऊष्मा से बचाकर उनकी पैदावार और गुणवत्ता की रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर फसलों के धसन और मिट्टी से निकलने वाली स्वाभाविक नमी से निर्मित सूक्ष्म-वातावरण ऊपर



स्थित सोलर पैनलों के तापमान को नियंत्रित रखता है। सिलिकॉन-आधारित सौर पैनलों की यह तकनीकी विडंबना है कि जैसे-जैसे उनका तापमान बढ़ता है, उनकी बिजली उत्पादन करने की दक्षता घटने लगती है। नीचे फसलों की हरियाली और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के कारण सोलर पैनलों का धरातलीय तापमान पाँच से दस डिग्री सेल्सियस तक कम बना रहता है, जिससे उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाती है। विज्ञान और प्रकृति का यह अनूठा तालमेल न केवल

ऊर्जा उत्पादन की दर को बढ़ाता है, बल्कि पैनलों की परिचालन अवधि को भी लंबा करता है। सामाजिक और आर्थिक धरातल पर, एग्रो-वोल्टिक्स भारतीय कृषि की सबसे बड़ी कमजोरी-आय की अनिश्चितता-पर सीधा प्रहार करता है। सदियों से भारतीय किसान मानसून की अनिश्चितता, चक्रवात, सूखा और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच अनिश्चितता का जीवन जीने को मजबूर रहा है। एग्रो-वोल्टिक्स प्रणाली किसान को केवल अन्नदाता के दायरे से निकालकर एक सशक्त ऊर्जादाता

को भी निर्माणशील बना सकता है।

के रूप में स्थापित करती है। सोलर पैनलों से उत्पादित अधिशेष बिजली को राज्य के विद्युत ग्रिडों को बेचकर या नेट-मीटरिंग नीतियों के तहत जमा करके किसान एक सुनिश्चित, मासिक और वर्षभर चलने वाली वित्तीय आय प्राप्त कर सकता है। यह सुनिश्चित आय प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसान के लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, खेत में ही उत्पादित इस हरित ऊर्जा का उपयोग सिंचाई पंपों को चलाने, सौर चालित शीतगृहों (कोल्ड स्टोरेज) के संचालन और स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग में किया जा सकता है। इससे महंगे डीजल और अनिश्चित ग्रिड बिजली पर किसान की निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाती है, जिससे खेती की परिचालन लागत में भारी कमी आती है और किसान का शुद्ध लाभार्थ कई गुना बढ़ जाता है। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी एग्रो-वोल्टिक्स की सफलता का मुख्य आधार उपयुक्त फसलों का चयन और सुदृढ़ इंजीनियरिंग संरचना है। इस तकनीक के तहत सोलर पैनलों को भूमि से कम से कम आठ से दस फीट की ऊँचाई पर इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि उनके नीचे ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों का संचालन बिना किसी बाधा के हो सके। प्रकाश-छाया के इस संयोजन में आंशिक छाया को पसंद करने वाली फसलें जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, आलू, गाजर, पत्तेदार सब्जियाँ, हल्दी, अदरक, और विविध औषधीय पौधे अत्यंत उत्कृष्ट पैदावार देते हैं। शुष्क और अर्ध-शुष्क इलाकों में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जैसे अग्रणी संस्थानों द्वारा किए गए व्यापक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि यह तकनीक न केवल बंजर और कम उपजाऊ भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने की अपार क्षमता रखती है, बल्कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने और क्षरित भू-भागों के पारिस्थितिक पुनरुद्धार में भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

